RNI No. 43038/1985 Postal Reg. No.: DL(C)-14/1434/2024-26, Posting Date: 28 & 29 of the Same Month

मूल्य: 10 रुपये

नेजाजी की जुबानी

विशुद्ध राष्ट्रवाद, पूर्ण न्याय और पक्षपात विहीनता के आधार पर भारत के मुक्ति हेतु सेना बन सकती है

जन गर्जन

वर्ष 39 अंक 8 हिन्दी मासिक नई दिल्ली अगस्त –2024 विक्रमी संवत्–2078 प्रधान संपादक: देवब्रत बिश्वास, वार्षिक – शुल्क: 100 रुपये

हमें अपने अस्तित्व की रक्षा हेतु पंथ–निरपेक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली आवश्यक

जी. देवराजन
महासचिव
ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक

ऐतिहासिक लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसा संबोधन दिया उससे यह बात उजागर हो गई कि पूर्व की भांति सरकार पर उनका नियंत्रण या दबदबा कायम है। अपने पूर्व के दोनों कार्यकालों में वे क्षेत्रीय राजनैतिक दलों को लेकर असहज, अलोचनात्मक और अलोकतांत्रिक रहे हैं। एक बार पुनः 'विकसित भारत 2047' का सब्जबाग दिखाते हुए मोदी ने ऐसा स्वप्न दिखाया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र, किसानों की खुशहाली, नारी सुरक्षा, देश में फैली असुरक्षा आदि पर प्रकाश डाला परन्तु विगत दस वर्षोंमें हमने किसानों का उत्पीड़न, नारी सुरक्षा के प्रति अरूचि और अप्रत्याशित रूप से बढ़ी हुई बेरोजगारी की समस्या के प्रति गंभीरता का घोर अभाव देखा है।

संविधान पर सवाल उठाते हुए और सर्वोच्च न्यायालय पर टिप्पणी करते हुए प्रधानमंत्री ने समान नागरिक संहिता का प्रश्न उठाया तथा इस तरफ आगे बढ़ने का आह्वान किया तथा कहा कि 'पंथ निरपेक्ष' और जो 'साम्प्रदायिक' तथा 'भेदभाव' बढ़ाने वाला नहीं हो और अभी का तो ऐसा ही है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा: ''हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक बार समान आचार संहिता पर चर्चा किया है। अनेक बार ऐसे आदेश दिए गए हैं जिससे आबादी के वृहद भाग में विश्वास जम गया और इसमें सत्यता भी है–कि आचार संहिता जिसके साथ हम लोग जी रहे हैं वह 'साम्प्रदायिक नागरिक संहिता' जिसमें भेदभाव उत्पन्न करने की प्रवृत्ति है।''

लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया संबोधन यह स्पष्ट करता है कि भाजपा व स्वयंसेवक संघ भारत के संविधान के प्रति आदर का भाव नहीं रखते हैं, देश की स्वतंत्रता के प्रति समर्पित महान स्वतंत्रता सेनानियों, संविधान सभा के सदस्यों, स्वातंत्रता संग्राम के संघर्षों से उपजे मूल्यों और संविधान निर्माता डा. भीम राव अम्बेडकर को लेकर श्रद्धा नहीं रखते हैं। हमारे विपक्ष अर्थात् 'इंडिया ब्लॉक' ने श्री मोदी द्वारा पंथ निरपेक्ष 'समान नागरिक संहिता' बनाए जाने की कडी आलोचना की, साथ ही वर्तमान नागरिक संहिता को 'साम्प्रदायिक' और 'भेदभाव मूलक' बताए जाने पर विपक्ष ने घोर आपत्ति दर्ज की है। विपक्ष ने ऐसी टिप्पणी को लेकर कहा है कि

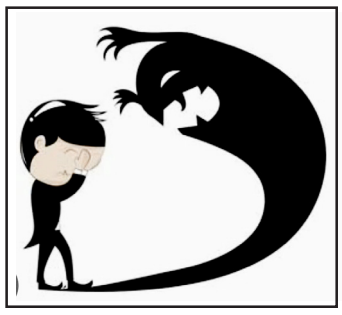

ऐसा कहकर श्री मोदी ने हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माता का 'बड़ा भारी अपमान' किया है। विपक्ष के नेताओं ने प्रधानमंत्री के संबोधन को गैर–जिम्मेदाराना बताया है तथा इतिहास की दृष्टि से देश की गरिमा गिराए जाने वाला बताया।

भारत के प्रधानमंत्री के रूप में श्री मोदी लगातार 11वीं बार लाल किले से संबोधित कर रहे थे। इतना लम्बा समय बीत जाने के बाद भी उनका संबोधन सुनकर लग रहा था कि वे अभी भी यह समझ नहीं सके हैं कि वे 140 करोड़ से अधिक देशवासियों के प्रधानमंत्री हैं जिसमें भाजपा को चुनाव में मत देने वाले तथा मत नहीं देने वाले विशाल आबादी के दोनों धड़े सम्मिलित हैं श्री मोदी को भाषण दिए जाने के स्थान और तिथि दोनों का ध्यान रखना चाहिए। ऐतिहासिक लाल किला सुप्रसिद्ध 'आजाद हिंद फौज' पर मुकदमे की सुनवाई के लिए याद किया जाता है जहां से आजादी के आंदोलन की नई धारा फूट पड़ी थी तथा 'नाविक विद्रोह' समेत देशव्यापी हड़ताल और जन आंदोलन की घटनाओं से राष्ट्रीय आंदोलन को बल मिला। श्री मोदी सदैव चुनावी मनोदशा में रहा करते हैं तथा सम्पूर्ण राष्ट्र के अभिभावक के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करने में असफल रहे। वे विभाजनकारी नीतियों को आगे बढ़ाते हैं तथा अपनी वाकपटुता के द्वारा हिन्दू ध्रुवीकरण को बढ़ाते हैं तथा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के एजेडे पर कार्य करतेहैं। वे वर्ष 2047 की बातें करते हैं जबकि वर्तमान में भयावह हो चुके बेरोजगारी के मुद्दे को सम्भालने में रूचि व क्षमता नहीं रखते हैं तथा देश के बहुलतावादी व विविधता से जुड़े प्रश्नों को हल कर पाने सक्षम नहीं है। 'पंथनिरपेक्ष' सिद्धान्त की आड़ लेकर वे हम सब पर 'विविधता की क्षमता' को सम्बल देने के बजाए एकरूपता थोपना चाहते हैं।

श्री मोदी ने आगेकहा: 'सरकार द्वारा सुधार का वादा 'कुछ दिनों की प्रशंसा पाने की नहीं है' बल्कि देश को मजबूती प्रदान करने की है। इसी कारण में यह कहता हूं कि हमारा सुधारात्मक प्रयास का मार्ग विकास का ब्लूप्रिंट है। यह सुधार, यह विकास, यह परिवर्तन महज चर्चा स्थल, बौद्धिक समाज और विद्वानों के मनोजरन का विषय नहीं है। हम इसे महज राजनैतिक बाध्यता के लिए नहीं कर रहे हैं...हमारा एकमात्र उद्देश्य–राष्ट्र प्रथम है।'' देशवासियों को उनके शब्दों पर भरोसा नहीं है। अपने दोनों कार्यकालों के दौरान उन्होंने देश के मजबूत सामाजिक और सांस्कृतिक ताने–बाने को भरपूर चोट पहुंचाई है। अनेक अवसरों पर

शेष पेज 2 पर...

असंतुलित बजट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत 2024–25 का केंद्रीय बजट असंतुलित है और 2023–24 के आर्थिक सर्वेक्षण में उल्लिखित आर्थिक वास्तविकताओं के साथ तालमेल बिठाने में विफल रहा है।

वित्त मंत्री द्वारा राजनीतिक कारणों से बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष वित्तीय सहायता की घोषणा संविधान द्वारा गारंटीकृत संघीय चरित्र की अवहेलना करती है, जबकि अन्य राज्यों की मांगों को पूरी तरह से खारिज कर देती है।

बजट में देश के सामने मौजूद गंभीर सामाजिक–आर्थिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए रचनात्मक और दीर्घकालिक प्रस्तावों का अभाव है। एक ओर, बजट में आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है, और दूसरी ओर, इसमें मुख्य रूप से ईंधन, खाद्य और उर्वरक पर सब्सिडी कम कर दी गई है, जिससे कीमतें और बढ़ेंगी। वित्त मंत्री उच्च राजस्व के बावजूद, बजट में राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए आनुपातिक रूप से सरकारी खर्च बढ़ाने के लिए तैयार नहीं हैं। यह सुझाव देना तर्कसंगत तर्क नहीं है कि सरकार खर्च बढ़ाए बिना रोजगार पैदा करेगी।

लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने के उपाय किए बिना आयात शुल्क कम करने या विदेशी निवेश की उम्मीद करने से कोई लाभ नहीं है। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए आवंटन में मामूली वृद्धि से किसानों को बहुत राहत नहीं मिलेगी। संघर्षरत किसानों की शिकायतों, जैसे ऋण माफी, कानूनी न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी), विपणन और भंडारण सुविधाओं के साथ–साथ पशुपालन, मछली पालन और मुर्गीपालन में किसानों के सामने आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों (सीटीयू) द्वारा रखे गए सभी प्रस्तावों को वित्त मंत्री द्वारा खारिज करना श्रमिकों के अधिकारों पर सीधा प्रहार है और जीडीपी के वास्तविक निर्माता के प्रति नकारात्मक रवैये को दर्शाता है। बजट एक अलग रेलवे बजट के महत्व को दोहराता है क्योंकि इस बजट में रेल यात्रियों की शिकायतों को दूर करने के लिए कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है। रेल सुरक्षा में सुधार, यात्रा सुविधाओं को बढ़ाने और रेलवे में रिक्तियों को भरने के लिए बजट में कोई प्रस्ताव नहीं है, जबकि रोजाना ट्रेन दुर्घटनाएं होती रहती हैं।

इस बजट का मुख्य लाभार्थी कॉर्पोरेट क्षेत्र है, जबकि एक बार फिर आम जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक सभी वर्गों के लोगों से बजट के जन–विरोधी प्रस्तावों के खिलाफ आवाज उठाने का आग्रह करता है।

संपादकीय

'विकसित भारत' की दुविधा

विविधता में एकता, विविध संस्कृतियों में एकता और अलग–अलग जीवन शैलियों में एकरूपता हमारे समाज का उज्जवल पक्ष है जो इसकी अन्तर्निहित शक्ति को स्पष्ट करता है जिसके बल पर हमने ब्रिटिश साम्राज्यवादी शक्ति से मुकाबला किया यद्यपि कि 'फूट डालो, राज करो' के सिद्धान्त के बल पर अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया। इस साम्राज्यवादी हथियार का आज भी प्रयोग हो रहा है तथा किसी न किसी रूप में साम्राज्यवादी ताकतें हम पर काबिज हैं। ये हर उम्र, समूह, कामगार वर्ग को तीखे तौर पर विघटित करते हैं कि हम असहाय दशा को प्राप्त हो चुके हैं तथा उचित स्कूली शिक्षा और तदन्तर रोजगार के अवसर नदारत हैं। हम अभी भी कृषि आधारित देश हैं और अच्छी शिक्षा एवं गरिमामय जीवन शेली की उपलब्धता उस समुदाय पर आधारित है जो मूलतः कृषि गतिविधियों पर आश्रित है।

इस वर्ष जून के प्रारम्भ में आए लोकसभा चुनाव के नतीजों से भाजपा आहत थी। भाजपा का मानना था कि आकर्षक जीडीपी के आंकड़े तथा कम्प्यूटरीकृत जनकल्याण सेवाओं को पहुंचाने से जनता प्रभावित हो जाएगी। परन्तु वास्तव में रोजी–रोटी आधारित आर्थिक तंत्र प्रभावकारी रहा। देश की 65 प्रतिशत आबादी युवा है और उसे बेहतर मजदूरी, सुनिश्चित सुरक्षा और उदीयमान भविष्य की चाहत है जो उचित व अनिवार्य है। अपने कृषि कार्यों और उत्पाद के एवज में हमारे संघर्षशील किसान बेहतर मूल्य और अच्छी आय की आकांक्षा रखते हैं जो उन्हें नहीं मिल रही है। 'ब्रेन ड्रेन' एक गंभीर समसया बन चुकी है। प्रतिभावान युवा बेहतर अवसरों की तलाश में विदेश पलायन करते रहे हैं। जिन देशों में युवा जाते हैं वे देश उनसे लाभान्वित होते हैं और हमारे देश के लिए अनेक चुनौतियां देते जाते हैं। विदेश मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार लगभग 25 लाख लोग प्रतिवर्ष पलायित कर जाते हैं जो भारत के विकास को कमजोर करते हैं, क्योंकि निपुण मानव संपदा का दोहन होता है। यही नहीं लगभग 23,000 भारतीय खरबपतियों ने वर्ष 2014 से 2018 के मध्य भारत छोड़ दिया ओर यह जानकारी विश्व बैंक ने 2018 में दी। वर्ष 2020 तक उच्च आय वर्ग से 2 प्रतिशत आबादी का स्थायी पलायन प्रतिवर्श हो चुका है। आगे की सही जानकारी नहीं है। पलायन व स्थायी पलायन से समस्या और दुरूह हो चुकी है।

हमारे देश में बेहतर शोध और विकास कार्य की सुविधा नहीं है तथा उचित कार्य बाल को मौका देने का आधार गायब है। अपने शिक्षा तंत्र को उन्नत करने में अक्षम हैं। रोजगार सृजन के अवसरों और निपुण कार्यबल को खपाने की अनुकूल परिस्थितियों को देने में हमें आगे आना आवश्यक है। भारतीय प्रवासियों द्वारा प्रेषित धन का भुगतान संतुलन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है जो व्यपार घाटे को कम करने में सहायता करता है। परन्तु अब इस ठोस समूह का चरित्र बदल रहा है तथा देश की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण अधिकांश प्रवासी विदेशों में अन्ततः बस जाने की ओर उन्मुख हो चुके हैं।

देश के अन्दर हम विभाजनकारी नीतियों को झेल रहे हैं तथा मोदी का 'विकसित भारत' महज एक नारा बन गया है जो लुभावना दर्शाया जा रहा है। 'फूट डालो, राज करो', हिन्दू ध्रुवीकरण और साम्प्रदायिकता का एजेंडा जारी है ऐसे में कैसे कोई बेहतर अवसर उपलब्धता के नाम पर एकजुटता बढ़ा सकता है? वास्तव में कामगार वर्ग के साथ न्यायोचित व्यवहार करके धर्म व जाति के ऊपर उठकर सबको एक किा जा सकता है। सही दिशा में कार्य कर करने की रणनीति सत्ता पक्ष में नहीं है। कथनी करनी में फर्क है। कहते कुछ और हैं तथा करते हैं सिर्फ आरएसएस के एजेंडे का कार्य। ऐसी दुविधा में हम सही राजनैतिक सोच को सामने लाना होगा तथा उस अनुकूल कार्य कर देश की युवा आबादी को प्रभावित करना होगा।

देश के अंदर प्रतिभा सर्जन व तद्नुकूल नीतियों व पहलकमिदयों द्वारा देश की युवा जनता को सम्बल देकर भारत को दुनिया के मानचित्र पर आकर्षक स्थल बनाया जाना चाहिए। इस प्रकार ब्रेन ड्रेन को न केवल रोका जा सकता है वरन 'ब्रेन गेन' की दिशा में हम अग्रसर होकर देश को 'विकसित भारत' का गौरव दिला सकते हैं जहां देश के युवा शिक्षित होकर रोजगार के लिए नहीं भटकेंगे। अन्यथा वर्तमान सत्ता पक्ष का यह 'विकसित भारत' लोकलुभवन नारा भर है क्योंकि इसके लिए आवश्यक इच्छा–शक्ति वर्तमान तंत्र और सत्ता पक्ष के पास नहीं है।

हमें अपने अस्तित्व की रक्षा हेतु...

पेज 1 से जारी...

हम सबने उनके अडियल और अलोकतांत्रिक कार्यशैली को देखा है। राजनीति में खानाजंगी करने के साथ उन्होंने देश की आर्थिक शक्ति को क्षीण करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज आर्थिक अवनति इस कदम है कि कभी भी हम औंधे मुंह गिर सकते हैं। देश की 65 प्रतिशत आबादी युवा है जिसे कार्य और रोजगार चाहिए। उनके कहे शब्दों और कार्यों में बड़ा अंतर है, अनेक बार उनके शब्द कड़वे, रूखे और दुबारा कहने में भी संकोच होता है जिसे यहां उद्घृत करना उचित नहीं है।

वस्तुतः किसी देश के लिए 'स्वतंत्रता दिवस' एक बड़ा अवसर और उत्सव का दिन होता है जब देशवासियों में आनन्द का प्रसार किया जाता है। श्री मोदी ने यह अवसर इस रूप में नहीं इस्तेमाल किया। यह कितना अच्छा हुआ होता यदि उन्होंने बजट में आवंटित विभिन्न मदों और नीतियों में धन तथा संबंधित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर प्रकाश डाला होता तथा 15 अगस्त के दिन का महत्व समझा होता।

विश्वसनीयता का संकट: श्री मोदी का जादू समाप्त हो चुका है। वे पहली बार अल्पमत की सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं और उनका असहज स्वरूप सामने दिखाई दे रहा है। वक्फ बोर्ड और नया ब्राडकास्टिंग के बिलों का हश्र इस बात को स्पष्ट कर रहा है। मोदी की कार्यशैली उनके जुमलों का जन मानस पर प्रभावहीन होना और उनके कथनी करनी का अन्तर इस रूप में सामने आया कि उनके तमाम प्रयतनों के बावजूद बहुमत नहीं मिला। इस गठजोड़ सरकार में मोदी–शाह जोड़ी की ताकत क्षीण हो रही है। तेलगूदेशम पार्टी और जनता दल (यू) को हल्के में नहीं लेकर मोदी सरका चला पायेंगे। मजबूत विपक्ष का उदय देश की संसद व सड़कों दोनों पर हो चुका है जिसके विश्लेषण की क्षमता सरकार पर भारी पड़ रही है तथा विपक्ष की चुनौती अकाट्य–सी हो चली है। इन सब परिवर्तनों के बावजूद मोदी सरकार राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यक्रम (एजेंडे) पर कार्य करती जा रही है या उस ओर बढ़ रही है और हमारे राजनैतिक सामाजिक, शैक्षिक व सांस्कृतिक क्षेत्रों में बचे हुए भागों के साम्प्रदायीकरण की ओर अग्रसर है।

अन्ततः मोदी के गत दो कार्यकाल के विपरीत इस बार विपक्ष सफलतापूर्वक संसदीय गतिविधियों पर अपना प्रभाव डाल रहा है तथा सरकार को रक्षात्मक होना पड़ रहा है। देश की जनता को उचित दिशा में मोड़कर आन्तरिक आसन्न खतरे के प्रति आगाह करने का समय आ चुका है। हमें एक पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली की आवश्यकता है अन्यथा हम सबका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इस दिशा में बहुत कार्य करना होगा। लोकतंत्र के तीनों स्तम्भों की रक्षा कर उन्हें शक्तिशाली करना अनिवार्य है तथा भयमुक्त व पक्षपातहीन मजबूत मीडिया का होना जरूरी है। सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण की प्रक्रिया पर रोक तथा शिक्षा व स्वास्थ्य को निजी हाथों में सौंपने की क्रिया पर अविलम्ब रोक आवश्यक है तथा बेरोजगारी की समसया के साथ किसानों की पीड़ा का निदान आवश्यक है। इस हेतु हम सबको आगे बढ़ना अनिवार्य है।

इजरायल द्वारा फिलिस्तीनियों के नरसंहार के खिलाफ विरोध

संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के बेशर्मी से उल्लंघन, गाजा में इजरायल द्वारा किए गए नरसंहार के खिलाफ आईसीजे के फैसलों और फिलिस्तीन के लोगों के खिलाफ इस तरह के नरसंहार को बढ़ावा देने के मद्देनजर, भारत में वामपंथी दल – सीपीआई (एम), सीपीआई, सीपीआई–एमएल, एआईएफबी और आरएसपी भारतीय लोगों से फिलिस्तीनी लोगों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करने और संयुक्त राज्य अमेरिका के समर्थन से इजरायल द्वारा किए जा रहे नरसंहार और अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने का आह्वान करते हैं। वामपंथी दल मांग करते हैं:

तत्काल युद्ध विराम और 1947 से पहले की सीमाओं वाले फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता और पूर्वी यरुशलम को राजधानी के रूप में मान्यता।

इजरायल पर और हथियारों और सैन्य उपकरणों के आयात और निर्यात पर तत्काल सैन्य प्रतिबंध लगाएं और सभी प्रकार के सैन्य सहयोग को रोकें।

इजरायल में औद्योगिक गतिविधि के लिए भारतीय श्रमिकों के सहयोग और आवाजाही पर तत्काल प्रतिबंध लगाएं।

राजनयिक वित्तीय और आर्थिक प्रतिबंधों सहित इजरायल पर कानूनी प्रतिबंध लगाएं।

इजरायल की रंगभेदी व्यवस्था को समाप्त करने और अपराधियों को जवाबदेह ठहराने के लिए रंगभेद के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की विशेष समिति को बुलाएँ।

इसके अलावा, हम भारत सरकार से मांग करते हैं:

1. इजरायल को सैन्य हथियारों और गोला–बारूद की आपूर्ति के लिए विभिन्न

भारतीय कंपनियों को सभी निर्यात लाइसेंस और अनुमतियाँ रद्द करें।

2. इजरायल से सभी हथियारों के आयात को रोकें।

3. औपनिवेशिक रंगभेद के सिद्धांतों के आधार पर इजरायल के अवैध सैन्य कब्जे और नरसंहार के साथ सभी प्रकार की मिलीभगत को समाप्त करें।

4. औपनिवेशिक रंगभेद के सिद्धांतों के आधार पर इजरायल के अवैध सैन्य कब्जे और नरसंहार के साथ सभी प्रकार की मिलीभगत को समाप्त करें। वामपंथी दल लोगों से यह भी आग्रह करते हैं कि वे स्वतंत्रता से पहले की हमारी विरासत को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा राजनीतिक और कूटनीतिक प्रतिरोध सुनिश्चित करें। वामपंथी दलों का मानना है कि पश्चिम एशिया की स्थिति एक ऐसे चरण में पहुँच गई है जहाँ वैश्विक लोकतांत्रिक राय को शांति और सम्मान की रक्षा के लिए खुद को मुखर करना चाहिए। वामपंथी दल देश भर में अपनी सभी पार्टी इकाइयों से आग्रह करते हैं कि वे 3 अगस्त को संयुक्त रूप से और स्वतंत्र रूप से भारतीय लोगों को प्रभावी ढंग से एकजुट करें।

सीताराम येचुरी (महासचिव, सीपीआई (एम)) डी. राजा (महासचिव, सीपीआई) जी. देवराजन (महासचिव, एआईएफबी) मनोज भट्टाचार्य (महासचिव, आरएसपी) दीपांकर भट्टाचार्य (महासचिव, सीपीआईएमएल (एल)।

वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव गुयेन फु ट्रोंग का निधन

एक युग का अंत हो गया

(वियतनाम समाचार एजेंसी द्वारा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, केंद्रीय समिति के महासचिव कामरेड जी. देवराजन के साथ साक्षात्कार, 19 जुलाई 2024, नई दिल्ली)

प्रश्न संख्या 1: आप वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव गुयेन फु ट्रोंग की पार्टी, राज्य और वियतनाम के लोगों के लिए उनकी भूमिका और योगदान, देश का निर्माण और विकास, लोगों के जीवन की देखभाल, पार्टी का निर्माण और सुधार, भ्रष्टाचार से लड़ना आदि विषयों पर मूल्यांकन कैसे करते हैं?

उत्तर: वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीवी) के महासचिव कॉमरेड गुयेन फु ट्रिंग देश के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं। 2011 में पदभार ग्रहण करने के बाद से, उनके कार्यकाल को सीपीवी को मजबूत करने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, भ्रष्टाचार से निपटने और वियतनामी लोगों की भलाई जैसे महत्वपूर्ण प्रयासों द्वारा चिह्नित किया गया है।

कॉमरेड गुयेन फु ट्रिंग का नेतृत्व सीपीवी की वैचारिक नींव और संगठनात्मक अखंडता को मजबूत करने में सहायक रहा है। तेजी से बदलती दुनिया में पार्टी की वैधता और प्रभावशीलता को बनाए रखने के महत्व को पहचानते हुए, कॉमरेड ट्रिंग ने समकालीन चुनौतियों के अनुकूल होने के साथ–साथ मार्क्सवादी–लेनिनवादी सिद्धांतों के पालन की आवश्यकता पर जोर दिया है। उनके नेतृत्व में, सीपीवी ने आंतरिक कमजोरियों को दूर करने के लिए 'आत्म–सुधार' की रणनीति अपनाई है। कॉमरेड ट्रिंग ने पार्टी की शासन क्षमताओं और आंतरिक अनुशासन में सुधार के उद्देश्य से कई प्रस्तावों का समर्थन किया है। उल्लेखनीय रूप से, 2011 में लागू किए गए पार्टी निर्माण पर सीपीवी के संकल्प 4 ने पार्टी के भीतर राजनीतिक पतन और भ्रष्टाचार के मुद्दों को संबोधित करने की मांग की। कज़ॅमरेड ट्रिंग ने इन प्रयासों का नेतृत्व किया है, एक 'स्वच्छ' और 'मजबूत' पार्टी का आह्वान किया है, जिसमें पार्टी की संरचना को सुव्यवस्थित करने, इसकी जवाबदेही तंत्र को बढ़ाने और इसकी नीतियों और प्रस्तावों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के प्रयास शामिल हैं। कॉमरेड ट्रिंग का कार्यकाल वियतनाम के वैश्विक मंच पर निरंतर आर्थिक उत्थान के साथ मेल खाता है। जबकि आर्थिक नीतियों की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी प्रधानमंत्री और आर्थिक मंत्रालयों के अधीन है, रणनीतिक दिशा और व्यापक नीतियों को निर्धारित करने में महासचिव की भूमिका महत्वपूर्ण है। कॉमरेड ट्रिंग ने आधुनिकीकरण को समाजवादी सिद्धांतों के साथ संतुलित करते हुए विकास को बनाए रखने के उद्देश्य से आर्थिक सुधारों का समर्थन किया है।

उन्होंने 'समाजवादी अभिविन्यास वाली बाजार अर्थव्यवस्था' की अवधारणा का समर्थन किया है, जो सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय संप्रभुता के साथ आर्थिक विकास को सुसंगत बनाने का प्रयास करती है। कॉमरेड ट्रिंग ने बुनियादी ढांचे के विकास, विदेशी निवेश और औद्योगिक उन्नति की आवश्यकता पर जोर दिया है, जबकि यह सुनिश्चित किया है कि आर्थिक लाभ समाज के विभिन्न क्षेत्रों में समान रूप से वितरित किए जाएं। उनके नेतृत्व ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में वियतनाम के बढ़ते एकीकरण को भी बढ़ावा दिया है, जिसका प्रमाण कई मुक्त व्यापार समझौते और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बढ़ती उपस्थिति है। शायद कॉमरेड गुयेन फु ट्रिंग के सबसे उल्लेखनीय योगदानों में से एक उनका जोरदार भ्रष्टाचार विरोधी अभियान (ब्लेजिंग फर्नेस) रहा है। कॉमरेड ट्रिंग के प्रशासन ने भ्रष्टाचार के प्रति शून्य–सहिष्णुता का रुख अपनाया है, जो उनके इस विश्वास को दर्शाता है कि भ्रष्टाचार सीपीवी की वैधता और राज्य की प्रभावशीलता को कमजोर करता है। कॉमरेड ट्रिंग के भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासों की विशेषता एक हाई–प्रोफाइल अभियान है, जिसने उच्च–श्रेणी के अधिकारियों और निचले स्तर के नौकरशाहों दोनों को निशाना बनाया है। भ्रष्टाचार विरोधी केंद्रीय संचालन समिति की स्थापना, जिसके वे अध्यक्ष हैं, इस अभियान का मुख्य केंद्र रही है। उनके निर्देशन में, समिति ने कई जांचों की देखरेख की है, जिसके परिणामस्वरूप प्रमुख हस्तियों पर मुकदमा चलाया गया और सख्त नियमन और निगरानी तंत्र लागू किए गए। इस अभियान को न केवल भ्रष्टाचार को कम करने का श्रेय दिया जाता है, बल्कि न्याय और ईमानदारी के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता में जनता का विश्वास बहाल करने का भी श्रेय दिया जाता है। कॉमरेड गुयेन फु ट्रिंग का वियतनामी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना सामाजिक न्याय के प्रति व्यापक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उनके प्रशासन ने गरीबी को कम करने, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा में सुधार करने और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से पहल को प्राथमिकता दी है।

कॉमरेड ट्रिंग ने ऐसी नीतियों की वकालत की है जिनका उद्देश्य सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करना है। उनके नेतृत्व में किए गए प्रयासों में सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में निवेश बढ़ाना शामिल है, जैसे कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच का विस्तार करना। सरकार ने पर्यावरण संबंधी मुद्दों को संबोधित करने में भी प्रगति की है, जिसमें प्रदूषण से निपटने और सतत विकास को बढ़ावा देने की पहल शामिल है। इन प्रयासों के माध्यम से, कॉमरेड ट्रिंग ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि वियतनाम की आर्थिक सफलता उसके लोगों के दैनिक जीवन में ठोस सुधार में तब्दील हो। अपने नेतृत्व के माध्यम से, कामरेड ट्रिंग ने समाजवाद के सिद्धांतों को बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हुए आधुनिक शासन की जटिलताओं को पार किया है कि आर्थिक प्रगति से सभी वियतनामी नागरिकों को लाभ मिले। उनके प्रशासन की सफलताएँ और चुनौतियाँ एक विकासशील समाजवादी राज्य में नेतृत्व की भूमिका के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं, जो राष्ट्रीय समृद्धि और सामाजिक न्याय की खोज में वैचारिक निष्ठा और व्यावहारिक शासन के बीच नाजुक संतुलन को दर्शाती हैं। कॉमरेड गुयेन फु ट्रिंग के योगदान में समाज में बदलाव लाने वाले नेताओं के सामने आने वाले अवसर और बाधाएं दोनों ही शामिल हैं, और उनकी विरासत का मूल्यांकन संभवतः वियतनाम के विकास की उपलब्धियों और मौजूदा चुनौतियों के संदर्भ में किया जाएगा।

प्रश्न संख्या 2: आप वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव गुयेन फु ट्रिंग के समाजवाद और समाजवादी–उन्मुख बाजार अर्थव्यवस्था के मुद्दों पर सैद्धांतिक योगदान का मूल्यांकन अन्य देशों के लिए सीखने के आधार के रूप में कैसे करते हैं?

उत्तर: वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीवी) के महासचिव कॉमरेड गुयेन फु ट्रिंग ने वियतनाम में समाजवाद की सैद्धांतिक नींव को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, विशेष रूप से समाजवादी–उन्मुख बाजार अर्थव्यवस्था विकसित करने के संदर्भ में उनका योगदान वियतनाम की अनूठी सामाजिक–आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों के लिए मार्क्सवादी–लेनिनवादी सिद्धांतों को अनुकूलित करने के लिए एक सूक्ष्म दृष्टिकोण को दर्शाता है। कॉमरेड ट्रिंग ने समाजवाद के लिए एक व्यावहारिक लेकिन सिद्धांतबद्ध दृष्टिकोण की वकालत की है जो मूल समाजवादी मूल्यों को त्यागे बिना सुधार की आवश्यकता पर जोर देता है। कॉमरेड ट्रिंग ने इस विचार को मजबूत किया है कि मार्क्सवादी–लेनिनवादी सिद्धांत को वियतनामी समाज की ठोस वास्तविकताओं के अनुकूल बनाया जाना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया है कि सीपीवी को विकसित सामाजिक–आर्थिक परिदृश्य पर प्रतिक्रिया करते हुए समाजवाद के मूलभूत सिद्धांतों को बनाए रखना चाहिए। इसमें राज्य के नेतृत्व वाले आर्थिक विकास और बाजार तंत्र के बीच संतुलन शामिल है, एक अवधारणा जिसे "दोई मोई" पर आधारित उनके भाषणों और लेखों में व्यक्त किया गया है। उनका दृष्टिकोण 'समाजवादी बाजार अर्थव्यवस्था' के सिद्धांत के साथ संरेखित है, जो बाजार की दक्षता को समानता और न्याय के समाजवादी लक्ष्यों के साथ एकीकृत करने का प्रयास करता है। कॉमरेड ट्रिंग के नेतृत्व में, 11वीं केंद्रीय समिति के संकल्प 4 ने सीपीवी के भीतर वैचारिक शुद्धता और आत्म–सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। संकल्प 4 का सैद्धांतिक आधार कॉमरेड ट्रिंग की इस धारणा को दर्शाता है कि प्रभावी समाजवादी शासन के लिए एक मजबूत, अनुशासित पार्टी आवश्यक है। वे वैचारिक विचलन और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पार्टी सिद्धांतों के निरंतर नवीनीकरण की वकालत करते हैं, समाजवादी सिद्धांतों को बनाए रखने में सैद्धांतिक कठोरता के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं। कॉमरेड ट्रिंग ने यह सिद्धांत बनाया है कि राज्य अर्थव्यवस्था को निर्देशित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो समाजवादी बाजार अर्थव्यवस्था मॉडल का एक महत्वपूर्ण पहलू है। उनका मानना है कि जबकि बाजार की ताकतें आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं, राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए कि विकास पूरे समाज को लाभान्वित करे और समाजवादी आदर्शों का पालन करे। यह परिप्रेक्ष्य एक सैद्धांतिक नवाचार है जो राज्य के नेतृत्व वाली विकास रणनीतियों के साथ बाजार की दक्षता को सुसंगत बनाने का प्रयास करता है। यह अवधारणा बाजार तंत्र को समाजवादी सिद्धांतों के साथ एकीकृत करती है और आर्थिक विकास के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है जिसे अन्य देश शिक्षाप्रद पा सकते हैं। कॉमरेड गुयेन फु ट्रिंग के सैद्धांतिक योगदान अन्य देशों के लिए कई सबक प्रदान करते हैं जो समाजवाद और बाजार अर्थव्यवस्थाओं के अपने संस्करणों की खोज या परिशोधन कर रहे हैं। उनका काम एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत करता है जिसे अन्य समाजवादी–उन्मुख देश अपने स्वयं के संदर्भों में अपना सकते हैं।

(अगले अंक में जारी रहेगा)

कल्याणकारी योजनाओं पर ध्यान देने पर हठधर्मिता

मोहित वर्मा
और
श्रवण एम.के.

कई कारणों से केंद्रीय बजट की कई लोगों ने कड़ी आलोचना की है। कल्याणकारी योजना के मोर्चे पर, सरकार एक बार फिर देश में हाशिए पर पड़े लोगों की सहायता करने वाली महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं पर व्यय बढ़ाने में विफल रही है। कल्याणकारी योजनाओं पर ध्यान देने से सरकार का हठधर्मितापूर्ण इन्कार हैरान करने वाला है, हमारे देश में जहां सरकार के अपने आंकड़ों के अनुसार, लगभग 34% आबादी प्रतिदिन रु. 100 से कम पर जीवित रहती है और 81 करोड़ से अधिक लोगों को जीवनयापन के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक (एनडीए) या एनडीए 3.0, कल्याणकारी योजनाओं में आवंटन को कम करके पिछले दो कार्यकालों में गठबंधन द्वारा जारी प्रवृत्ति को बनाये रखता हुआ प्रतीत होता है – जैसा कि बजट पत्रों के आधार पर नीचे दिए गए विश्लेषण में दिखाया गया है। प्रमुख कल्याणकारी योजनाएँ, अपर्याप्त वित्तपोषण सरकार की दो सबसे बड़ी कल्याणकारी योजनाएँ, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एएफएसए) (खाद्य सब्सिडी) ने 2014–15 से लगातार जीडीपी के हिस्से के रूप में अपने बजट आवंटन में गिरावट देखी है, कोविड–19 महामारी के वर्षों में जब सरकार को एक बड़ी आपदा को टालने के लिए इन दो योजनाओं पर निर्भर रहना पड़ा है। मनरेगा हर ग्रामीण परिवार को 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देता है, जबकि खाद्य सब्सिडी लगभग दो–तिहाई आबादी को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है।

पिछले साल एनएफएसए का व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 0.72% था, जबकि इस साल यह घटकर सकल घरेलू उत्पाद का 0.63% रह गया है। देश में यह वास्तव में एक विचित्र निर्णय है, जहाँ 100 करोड़ से अधिक लोग स्वस्थ आहार नहीं ले सकते हैं और जहाँ लगभग 50% लोग दिन में तीन बार भोजन कर पाते हैं। इसी तरह, इस वर्ष मनरेगा के लिए आवंटित बजट सकल घरेलू उत्पाद का 0.26% है, जबकि पिछली बार यह 0.29% आवंटित किया गया था। सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में इन दोनों योजनाओं के लिए आज संयुक्त बजट आवंटन 2014–15 की तुलना में जब एनडीए ने पहली बार सत्ता संभाली थी से 25% कम है, ग्रामीण वास्तविक मजदूरी में स्थिरता और मनरेगा के व्यवस्थित रूप से कम वित्तपोषण के साथ, यह कोई आश्चर्य नहीं है कि देश भर में ग्रामीण संकट बढ़ रहा है। गरीबी रेखा से नीचे विधवाओं, बुजुर्गों और विकलांग व्यक्तियों जैसे कमजोर समूहों को भी बजट में नजरअंदाज कर दिया गया। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, जो उल्लिखित समूहों और साथ ही उन परिवारों को मौद्रिक सहायता प्रदान करता है, जिन्होंने अपने कमाने वाले को खो दिया है, के बजट में आवंटन में कोई वृद्धि नहीं हुई। इस वर्ष इसका बजट आवंटन नाममात्र के संदर्भ में पिछले वर्ष के समान ही है। सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में इसका व्यय 2014–15 से आधा होकर 0.06% से 0.03% हो गया है। इस योजना के तहत बुजुर्गों को 200 रुपये प्रति महीने और विधवाओं को 300 रुपये प्रति महीने की मामूली पेंशन दी जाती है – यह राशि दर्जनों अर्थशास्त्रियों के बार–बार अनुरोध के बावजूद 2006 से नहीं बढ़ाई गई है। अगर इन कमजोर समूहों को सिर्फ राज्य के भरोसे छोड़ दिया जाए तो वे 30 रुपये प्रतिदिन की गरीबी रेखा पर भी कम से कम 66% गरीबी रेखा से नीचे रह रहे होंगे।

कल्याण और पोषण योजनाएँ

हाल ही में, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने संसद में स्वीकार किया कि भारत में पाँच वर्ष से कम आयु के 50% से अधिक बच्चे दीर्घकालिक कुपोषण से पीड़ित हैं। इसके अलावा, भारतीय महिलाओं और बच्चों में एनीमिया की दर वैश्विक औसत से क्रमशः 20% और 15% अधिक है। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 एक कल्याणकारी योजना है जिसका उद्देश्य बाल कुपोषण और भूख से निपटना है। आंगनवाड़ी कार्यक्रम को 2021–22 में प्रधानमंत्री की समग्र पोषण योजना (पोषण) अभियान और किशोरियों के लिए पोषण योजना के साथ मिला दिया गया था। हालाँकि, परिवर्धन के साथ भी, इसके लिए आवंटित बजट 2014–15 से आधे से अधिक घट गया है – जीडीपी के 0.13% से हाल के बजट में जीडीपी का 0.06% हो गया है। स्कूल जाने वाले बच्चों में कुपोषण और भूख को दूर करने के लिए सरकार मिड–डे मील (एमडीएम) कार्यक्रम चलाती है। एमडीएम कार्यक्रम देश के लगभग 12 करोड़ बच्चों को कवर करता है। कक्षा में उपस्थिति बढ़ाने और शैक्षिक और पोषण संबंधी परिणामों में कार्यक्रम की कई सफलताओं के बावजूद, इसके लिए निर्धारित धनराशि 2014–15 से जीडीपी के हिस्से के रूप में आधी हो गई है। इसके अलावा, वित्त मंत्रालय ने तमिलनाडु में किए गए वादे के बावजूद फंड की कमी का हवाला देते हुए 2021 में स्कूल में नाश्ते की योजना को खारिज कर दिया। हमारे बच्चों के सामने गंभीर कुपोषण संकट को देखते हुए, यह जरूरी है कि हम इन कार्यक्रमों का दायरा बढ़ाएँ और अपने बच्चों को अधिक पौष्टिक भोजन प्रदान करें।

शिक्षा (प्राथमिक और माध्यमिक) पर केंद्रीय व्यय का सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सा भी पिछले साल के 0.25% से इस साल घटकर 0.22% रह गया है। हालांकि प्राथमिक शिक्षा में नामांकन दर उच्च है, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता और बुनियादी ढांचे के मामले में हमें अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। इसलिए, यह चिंताजनक है कि सकल घरेलू उत्पाद में शिक्षा का हिस्सा 2014–15 में 0.37% से घटकर आज 0.22% हो गया है। यहां एकमात्र राहत स्वास्थ्य के लिए बजट आवंटन है, जिसमें मामूली वृद्धि देखी गई। 2014–15 से, सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में स्वास्थ्य मंत्रालय को आवंटित बजट का हिस्सा उस समय के 0.25% से बढ़कर इस साल 0.28% हो गया है। हालांकि, यह वृद्धि ऐसे देश में पर्याप्त नहीं है जहां स्वास्थ्य पर जेब से किया जाने वाला खर्च बहुत अधिक है और हर साल लाखों लोग गरीबी में धकेले जाते हैं। सभी उल्लिखित योजनाओं/विभागों के लिए बजट आवंटन 2014–15 में सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में 2.1% से घटकर इस वर्ष केवल 1.53% रह गया है। तथ्य यह है कि यह आज के सकल घरेलू उत्पाद के 4.31% से लगभग तीन गुना था। 2020–21 के कोविड–19 महामारी वर्ष में, इन योजनाओं की जीवन शक्ति को रेखांकित करता है। एक अनुमान के अनुसार, सरकार ने 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स दरों में कटौती के बाद से 8 लाख करोड़ से अधिक के कर राजस्व को छोड़ दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि कर कटौती के कारण राजकोषीय स्थान में परिणामी कमी को समायोजित करने के लिए गरीबों और कमजोर लोगों की बलि दी गई है। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि भारत का मानव विकास सूचकांक में 132वां स्थान है, और आज यह ब्रिटिश शासन के दौरान की तुलना में अधिक असमान है, जैसा कि विश्व असमानता प्रयोगशाला की एक नई रिपोर्ट में बताया गया है। इसके विपरीत, यूपीए काल अगर एनडीए सरकार अपने विकसित भारत के सपनों को लेकर गंभीर है तो उसे यह समझना होगा कि विकसित समाज का रास्ता उसके सबसे गरीब नागरिकों के पेट और कलम से होकर जाता है। कोई भी सभ्य समाज तब तक विकसित नहीं माना जा सकता जब तक कि उसकी आबादी का एक बड़ा हिस्सा सम्मान की जिंदगी जीने में असमर्थ हो। शायद एनडीए सरकार को संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकारों के उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए, जिन्होंने न केवल नई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की बल्कि समय के साथ अपने बजट आवंटन में भी लगातार वृद्धि की।

(सौजन्यः द हिंदू)

नेताजी के कथित अवशेषों को वापस लाने की मांग दुर्भावनापूर्ण है

ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का मानना है कि नेताजी के कथित अवशेषों को वापस लाने की हालिया मांग दुर्भावनापूर्ण और एक बड़ी साजिश का हिस्सा है।

देश में दशकों से इस मुद्दे पर बहस चल रही है और इसे निराधार बताया गया है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ केंद्र निहित स्वार्थों और स्वार्थी उद्देश्यों के चलते समय–समय पर इस मुद्दे को उठाते रहते हैं।

यह एक तथ्य है कि नेताजी के लापता होने पर न्यायमूर्ति मनोज कुमार मुखर्जी (पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश) की अध्यक्षता में गठित अंतिम जांच आयोग ने इस बात को पुख्ता तौर पर साबित कर दिया था कि नेताजी की मौत कथित विमान दुर्घटना में नहीं हुई थी। यह निष्कर्ष इसलिए निकाला गया क्योंकि 18 अगस्त 1945 को ताइहोकू हवाई अड्डे (जो अब ताइवान में है) पर कोई विमान दुर्घटना नहीं हुई थी। आयोग की रिपोर्ट में सबूत के तौर पर ताइवान सरकार के आधिकारिक रिकॉर्ड शामिल हैं। इसके अलावा, यह बताया गया कि 18 अगस्त 1945 से एक सप्ताह पहले और बाद में भी कोई विमान दुर्घटना नहीं हुई थी। रेंकोजी मंदिर में रखी राख भी नेताजी से असंबंधित पाई गई, क्योंकि उनकी पहचान ताइवान के एक सैनिक इचिरो ओकुरा के अवशेषों के रूप में की गई, जिनकी मृत्यु अगस्त 1945 में हुई थी। आयोग की व्यापक जांच, जिसमें जापान, ताइवान, रूस और इंग्लैंड का दौरा शामिल था, इस निष्कर्ष पर पहुंची कि नेताजी की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना में नहीं हुई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित पार्टी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने केंद्र सरकार से न्यायमूर्ति मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार करने और सभी अटकलों और षड्यंत्रों को समाप्त करने का आग्रह किया। पार्टी 18 अगस्त 1945 के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ जो हुआ, उसके बारे में सच्चाई को उजागर करने के लिए एक आयोग के गठन की भी मांग करती है, तथा केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों के पास नेताजी, फॉरवर्ड ब्लॉक, आईएनए और आजाद हिंद सरकार से संबंधित जो दस्तावेज हैं, उन्हें बिना किसी देरी के सार्वजनिक करने के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन की भी मांग करती है।

बांग्लादेश में शांति बहाल होनी चाहिए

(फॉरवर्ड ब्लॉक के महासचिव जी. देवराजन ने 6 अगस्त 2024 को निम्नलिखित बयान जारी किया है)

आरक्षण को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन ने बांग्लादेश में महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम को जन्म दिया। बाद में, यह देखा गया कि छात्रों द्वारा शुरू किए गए विरोध को अंततः जनता ने अपने नियंत्रण में ले लिया। देश में बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई और व्यापक गरीबी ने विरोध को और तीव्र कर दिया।

सरकार ने विरोध को लोकतांत्रिक तरीके से निपटाने के बजाय सेना और पुलिस का इस्तेमाल करके इसे दबाने की कोशिश की। सरकार को भ्रम था कि वह कर्फ्यू लगाकर, विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करके और बल प्रयोग करके हड़ताल को दबा सकती है। गोलीबारी में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। जैसे–जैसे सरकार के दमनकारी उपाय बढ़ते गए, प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री शेख हसीना के तत्काल इस्तीफे की मांग की। आखिरकार, प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के आवास पर धावा बोल दिया।

बांग्लादेश में राजनीतिक उथल–पुथल के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना के अचानक इस्तीफे और भाग जाने से देश की स्थिरता को लेकर काफी चिंताएँ पैदा हो गई हैं।

जैसे–जैसे राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है, सभी हितधारकों के लिए बातचीत में शामिल होना और संकट का शांतिपूर्ण समाधान तलाशना जरूरी है। बांग्लादेश में शांति बहाल करना एक बहुआयामी प्रयास है जिसके लिए समाज के सभी क्षेत्रों से सहयोग, प्रतिबद्धता और करुणा

की आवश्यकता है। संवाद को बढ़ावा देकर, लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करके, सामाजिक–आर्थिक चुनौतियों का समाधान करके और सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देकर, बांग्लादेश में एक स्थिर भविष्य का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।

राजनीतिक परिदृश्य को स्थिर करने के लिए, कानून के शासन को सुदृढ़ करना और लोकतांत्रिक मानदंडों को बनाए रखना जरूरी है। यह सुनिश्चित करना कि कानून निष्पक्ष रूप से काम करे और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे, जनता के विश्वास को फिर से बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। राजनीतिक हिंसा और मानवाधिकार उल्लंघन के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने के लिए स्वतंत्र न्यायिक प्रक्रियाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

बांग्लादेश सांस्कृतिक विविधता से समृद्ध राष्ट्र है और दीर्घकालिक शांति के लिए सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देना जरूरी है। विभिन्न जातीय, धार्मिक और सांस्कृतिक समुदायों के बीच समझ और सम्मान को बढ़ावा देने के प्रयास तनाव को कम कर सकते हैं और एक मजबूत राष्ट्रीय पहचान बना सकते हैं।

देश में जब गंभीर सामाजिक–राजनीतिक संकट हो, तो लोगों को धार्मिक प्रतिद्वंद्विता को बढ़ावा देकर देश को अस्थिर करने के दुर्भावनापूर्ण प्रयासों के प्रति सतर्क रहने के लिए तैयार रहना चाहिए। पार्टी कार्यालयों और धार्मिक संस्थानों को ध्वस्त करना और राष्ट्रपिता बंगबंधु मुजीब रहमान की मूर्ति को नष्ट करना न केवल निंदनीय कार्य हैं, बल्कि इससे देश में तनाव ही बढ़ेगा। निहित स्वार्थों वाली साम्राज्यवादी ताकतों के हस्तक्षेप के खिलाफ भी अत्यधिक सतर्कता की आवश्यकता है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक सभी से, विशेष रूप से बांग्लादेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से, लोगों के बीच विभाजन पैदा करने के गुप्त उद्देश्य से फैलाई जाने वाली खबरों के जाल में न फंसने का आग्रह करता है।

एआईएफबी आंध्र प्रदेश राज्य कर्मचारी सम्मेलन: एआईएफबी ने पुनर्गठन अधिनियम के तहत अधिकारों की पूर्ति की मांग की

ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के महासचिव जी. देवराजन ने केंद्र और राज्य सरकारों को चेतावनी दी है कि वे प्रत्यावर्तन अधिनियम के अनुसार आंध्र प्रदेश राज्य के सभी अधिकारों को पूरा करें या फिर जनांदोलन का सामना करें।

वे 4 अगस्त 2024 को आईएमए हॉल, कडप्पा में आयोजित राज्य कर्मचारी बैठक को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने इस बात पर निराशा व्यक्त की कि हाल के विधानसभा और संसद सत्रों में किसी भी नेता ने विशेष दर्जे की मांग नहीं उठाई। कामरेड देवराजन ने इस बात पर जोर दिया कि विशेष दर्जा मिलने से राज्य में अधिक उद्योग, रोजगार के अवसर और समग्र विकास होगा। उन्होंने विशाखापत्तनम इस्पात उद्योग के निजीकरण के निर्णय की आलोचना की और प्रत्यावर्तन अधिनियम में विशाखा रेलवे जोन और कडप्पा इस्पात उद्योग की उपेक्षा पर अफसोस जताया।

उन्होंने विशेष दर्जा हासिल करने और रायलसीमा में विशाखा इस्पात उद्योग स्थापित करने के लिए एक अंतर–दलीय आंदोलन का आग्रह किया, जिससे बेहतर रोजगार के अवसर मिलेंगे और क्षेत्र में पलायन, अकाल और आत्महत्या कम होगी।

बैठक की अध्यक्षता कॉम. सुभाष चंद्र रेड्डी ने की। कॉमरेड पी.वी. सुंदर रामाराजू ने संगठनात्मक और राजनीतिक रिपोर्ट पेश की। कॉमरेड असीम बाशा, कॉमरेड जयवर्धन, कॉमरेड (डा.) प्रवल्लिका, कॉमरेड चौतन्य, कॉमरेड सुब्बम्मा, कॉमरेड रवींद्रनाथ, कॉमरेड राधाकृष्ण, जे.वी. नरसिंह मूर्ति, कॉमरेड वी.वी.एम. राजू, कॉमरेड राज नायडू आदि ने बैठक में बात की। 11 जिलों के एआईएफबी नेताओं और जन मोर्चो के नेताओं ने भाग लिया।

कॉमरेड बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन

देश की वामपंथी और प्रगतिशील ताकतों के लिए एक बड़ी क्षति

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के वरिष्ठ नेता और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री कॉमरेड बुद्धदेव भट्टाचार्य के दुखद निधन पर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की केंद्रीय कमेटी ने अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है।

कॉमरेड बुद्धदेव भट्टाचार्य बंगाल के राजनीतिक परिदृश्य में एक प्रमुख वामपंथी व्यक्ति थे। उन्होंने पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकारों के कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान बंगाल के कृषि–औद्योगिक विकास के लिए उठाए गए कदमों को हमेशा याद किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और विभिन्न विभागों के कैबिनेट मंत्री के रूप में, उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और पद की गरिमा को बनाए रखा।

माकपा नेता के रूप में उन्होंने हमेशा धर्मनिरपेक्ष साख बनाए रखी और गरीबों और मजदूर वर्ग के प्रति उनके उदार स्वभाव और समझौताहीन रवैये ने लोगों को उनकी राजनीतिक विचारधाराओं के बावजूद आकर्षित किया। सामाजिक न्याय के प्रति उनकी दृष्टि और प्रतिबद्धता ने कई लोगों को प्रेरित किया। बंगाल में

वामपंथी एकता को मजबूत करने में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। मार्क्सवाद और समाजवाद के सिद्धांतों के प्रति उनका समर्पण और पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए उनके अथक प्रयासों ने हमारे समाज पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उनकी विरासत समानता और प्रगति की खोज में भावी पीढ़ियों का मार्गदर्शन और प्रभाव करती रहेगी।

कॉमरेड बुद्धदेव भट्टाचार्य, जिनका बंगाल के जीवंत सांस्कृतिक क्षेत्र पर गहरा प्रभाव था, के निधन से निस्संदेह उस क्षेत्र में एक बड़ा शून्य पैदा हो गया है।

वे एक सज्जन व्यक्ति और मूल रूप से एक योद्धा थे। उन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के कई वरिष्ठ नेताओं और नई पीढ़ी को उनके द्वारा उचित अवसरों पर की गई चर्चाओं और सुझावों से सीख लेनी चाहिए, जब उन्हें निर्णायक राजनीतिक निर्णय लेने हों। उनका निधन न केवल सीपीआई (एम) के लिए बल्कि देश के वामपंथी और प्रगतिशील आंदोलन के लिए भी एक बड़ी क्षति है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक कॉमरेड बुद्धदेव भट्टाचार्य की शानदार यादों को संजोते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है और सीपीआई (एम) के सभी कार्यकर्ताओं और उनके निधन पर शोक व्यक्त करने वाले सभी लोगों के साथ दुख में शामिल होता है।

वामपंथी दलों ने 31 जुलाई 2024 को हैदराबाद, तेलंगाना के सुंदरय्या कला केंद्र में धार्मिक कट्टरता पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया।

आंध्र प्रदेश के कडप्पा और नेल्लोर के एआईएसबी कार्यकर्ताओं ने छात्र समुदाय के विभिन्न मुद्दों पर धरना आयोजित किया।

करीम नगर जिले, तेलंगाना के सरकारी सिविल अस्पताल के कर्मचारियों ने टीयूसीसी के बैनर तले 2 अगस्त 2024 को अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की।

टीयूसीसी सहित केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की संयुक्त कार्रवाई समिति ने 3 अगस्त 2024 को पुणे में असंगठित और ठेका श्रमिकों का एक सम्मेलन आयोजित किया है।

अखिल भारतीय अग्रगामी किसान सभा सहित किसान सभाओं ने किसानों और कृषि श्रमिकों की विभिन्न मांगों पर 2 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश के भदोही में डीएम कार्यालय के सामने एक किसान रैली का आयोजन किया।

78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वीर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि। एआईएफबी के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय नेताजी भवन में एक विशेष समारोह आयोजित किया गया।

अखिल भारतीय अग्रगामी महिला समिति बंगाल राज्य समिति की बैठक 3 अगस्त 2024 को हेमंत बसु भवन, कोलकाता में आयोजित की गई।

उत्तर बंग उन्नयन संग्राम समिति (एआईएफबी के तत्वावधान में उत्तर बंगाल विकास कार्य समिति) ने 4 अगस्त 2024 को जलपाईगुड़ी नेताजी फाउंडेशन में उत्तर बंगाल के विभिन्न विकासात्मक मुद्दों पर एक बैठक आयोजित की है और वैधानिक उत्तर बंगाल विकास परिषद के गठन और उत्तर बंगाल के सभी क्षेत्रों में समावेशी और व्यापक विकास के लिए अन्य मांगों की मांग की है। उत्तर बंगाल जिलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

15–16 अगस्त 2024 को मालदा (पश्चिम बंगाल) और वाराणसी (उत्तर प्रदेश) में नेताजी प्रदर्शनी।

16 और 17 अगस्त 2024 को आरजी कर मेडिकल कॉलेज, कोलकाता में हुई नृशंस हत्या के खिलाफ रैलियों में बंगाल और आंध्र प्रदेश के एआईएफबी, एआईएसबी, एआईवाईएल और एआईएएमएस कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया।

कर्नाटक खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम लोडिंग और अनलोडिंग मजदूर गडग जिला सम्मेलन 28–07–2024

अगस्त क्रांति दिवस (9 अगस्त) पूरे देश में सीटीयू, प्रगतिशील ताकतों, राजनीतिक दलों और नागरिक समाज संगठनों द्वारा मनाया जाता है। एआईएफबी और टीयूसीसी इकाइयों ने पुणे, दिल्ली, कोलकाता, पटना, भुवनेश्वर, सिलचर (असम), गुवाहाटी, दिनहाटा (बंगाल), लखनऊ, मदुरै (तमिलनाडु), कोच्चि (केरल), बॉम्बे आदि में संयुक्त आंदोलन में भाग लिया।

अखिल भारतीय अग्रगामी महिला समिति केरल राज्य समिति की बैठक 18 अगस्त 2024 को त्रिवेंद्रम में हुई।

9 अगस्त 2024 को कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज में एक युवा महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के खिलाफ पूरे देश में, विशेष रूप से महिलाओं द्वारा स्वतःस्फूर्त बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। एआईवाईएल, एआईएएमएस और एआईएसबी के कार्यकर्ता पूरे बंगाल में सभी विरोध कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। पीड़िता के लिए न्याय की मांग करते हुए 14 अगस्त की आधी रात को बंगाल के शहरों में महिलाओं और लड़कियों ने रैली निकाली। दिल्ली में 14 अगस्त की मध्य रात्रि को एम्स के सामने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया।

वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी को शोक संदेश

केंद्रीय कमेटी,
वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी को।
दिनांक 20 जुलाई 2024
प्रिय साथियों,

अत्यंत दुख और भारी मन से ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की केंद्रीय कमेटी हमारे सम्मानित साथी, महासचिव गुयेन फु ट्रिंग के निधन पर वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी और वियतनाम के लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है।

कॉमरेड गुयेन फु ट्रिंग वैश्विक समाजवादी आंदोलन में एक महान हस्ती थे, वे एक दृढ़ नेता थे जिनकी दूरदर्शिता, समर्पण और मार्क्सवादी–लेनिनवादी सिद्धांतों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता ने वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी को गहन परिवर्तन और उन्नति के दौर से गुजारा। उनके नेतृत्व की विशेषता एक गहरी वैचारिक अखंडता, रणनीतिक दूरदर्शिता और वियतनामी लोगों और व्यापक वैश्विक समुदाय की भलाई के लिए एक मानवीय प्रतिबद्धता थी।

कॉमरेड ट्रिंग के नेतृत्व में, वियतनाम ने विकास और प्रगति के एक उल्लेखनीय युग का अनुभव किया। समाजवाद के सिद्धांतों के प्रति उनके समर्पण और आर्थिक सुधार के प्रति व्यावहारिक दृष्टिकोण के कारण 'समाजवादी–उन्मुख बाजार अर्थव्यवस्था' का कार्यान्वयन हुआ, जिसने बाजार की दक्षता को समानता और न्याय के समाजवादी आदर्शों के साथ सामंजस्य स्थापित किया। इस अभिनव मॉडल ने न केवल वियतनाम के विकास के लिए एक मार्ग के रूप में कार्य किया, बल्कि आधुनिक अर्थव्यवस्था की मांगों के साथ समाजवादी सिद्धांतों को समेटने का प्रयास करने वाले अन्य देशों के लिए एक प्रेरक उदाहरण के रूप में भी कार्य किया। भ्रष्टाचार का मुकाबला करने, पारदर्शिता की वकालत करने और वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी की वैचारिक शुद्धता सुनिश्चित करने में कॉमरेड ट्रिंग के अथक प्रयास उनके नेतृत्व के लिए प्रमुख बिन्दु थे। उनका भ्रष्टाचार विरोधी अभियान, जिसने दृढ़ निश्चय के साथ उच्च–स्तरीय भ्रष्टाचार को लक्षित किया, शासन में न्याय और जवाबदेही के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इस संबंध में उनका काम दुनिया भर में प्रगतिशील आंदोलनों के लिए एक प्रकाशस्तंभ रहा है, यह दर्शाता है कि सिद्धांतबद्ध नेतृत्व किसी भी समाजवादी सरकार के सामने आने वाली सबसे कठिन चुनौतियों का समाधान कर सकता है।

अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के क्षेत्र में, कॉमरेड ट्रिंग एक सम्मानित राजनेता थे जिन्होंने बहुपक्षवाद, वैश्विक एकजुटता और सांस्कृतिक कूटनीति का समर्थन किया। प्रमुख वैश्विक शक्तियों के साथ वियतनाम के संबंधों को मजबूत करने, आसियान के माध्यम से क्षेत्रीय एकीकरण की वकालत करने और सांस्कृतिक आदान–प्रदान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों ने वैश्विक मंच पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा है। इन प्रयासों के माध्यम से, कॉमरेड ट्रिंग ने 21वीं सदी की चुनौतियों का समाधान करने में शांतिपूर्ण सह–अस्तित्व, आपसी सम्मान और सामूहिक कार्रवाई के महत्व को मजबूत किया। कॉमरेड गुयेन फु ट्रिंग की मृत्यु न केवल वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए बल्कि पूरे वैश्विक समाजवादी आंदोलन के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। उनके निधन से एक ऐसा शून्य पैदा हो गया है जिसे वे सभी लोग गहराई से महसूस करेंगे जो उनके नेतृत्व, दूरदर्शिता और समाजवाद और न्याय के आदर्शों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता से प्रेरित हुए हैं। जैसा कि हम अपने सम्मानित कॉमरेड के निधन पर शोक मना रहे हैं, हम उनकी विरासत का भी जश्न मना रहे हैं – एक ऐसी विरासत जो सैद्धांतिक नेतृत्व, अभिनव शासन और समाजवाद के लिए एक दृढ़ समर्पण द्वारा परिभाषित की गई है। कॉमरेड ट्रिंग का योगदान दुनिया भर के समाजवादियों और प्रगतिवादियों की भावी पीढ़ियों को प्रेरित और मार्गदर्शन करना जारी रखेगा। दुख की इस घड़ी में, हम वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी और वियतनाम के लोगों के प्रति अपनी हार्दिक एकजुटता और समर्थन व्यक्त करते हैं। हम महासचिव गुयेन फु ट्रिंग की स्मृति का सम्मान करने और सभी के लिए एक न्यायपूर्ण, समान और समाजवादी भविष्य बनाने के उनके काम को जारी रखने में आपके साथ खड़े हैं। उनकी आत्मा को शाश्वत शांति मिले और उनकी विरासत उन सभी लोगों के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में चमकती रहे जो एक बेहतर दुनिया के लिए प्रयास करते हैं। हम कॉमरेड गुयेन फु ट्रिंग की महान यादों पर अपना झंडा और बैनर झुकाते हैं। कॉमरेड गुयेन फु ट्रिंग अमर रहें।

सादर,
हस्ताक्षर/–
(जी. देवराजन) महासचिव

आर.जी. कर निर्मम हत्या: एक राष्ट्रीय शर्म

9 अगस्त को कोलकाता के सरकारी आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार हॉल के अंदर एक 31 वर्षीय स्नातकोत्तर डाक्टर के साथ बेरहमी से बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई, जिससे पूरे देश में आक्रोश फैल गया। नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी सरकार के मामले को संभालने को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रही हैं। 13 अगस्त 2024 को, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पुलिस की जांच से असंतुष्ट होकर मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दिया। उन्होंने राज्य पुलिस द्वारा अपनी जांच जारी रखने पर सबूतों के नष्ट होने की संभावना को भी चिह्नित किया। स्वतः संज्ञान लेते हुए, सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने प्रशिक्षु डॉक्टर के "भयानक" बलात्कार और हत्या पर गहरी चिंता व्यक्त की है और कार्यस्थलों पर डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए तौर–तरीकों पर काम करने के लिए 9 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है। हत्या की शिकार युवा डॉक्टर के माता–पिता का कहना है कि उन्हें विभाग से फोन आया था कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। मां ने कहा कि शव को देखकर कोई भी बता सकता था कि यह हत्या है। हालांकि, पुलिस ने दावा किया कि उन्होंने इसे कभी आत्महत्या नहीं कहा। पोस्टमार्टम में पीड़िता के शरीर पर गंभीर चोट के निशान मिले। इन निष्कर्षों के आधार पर, कुछ डॉक्टरों ने निष्कर्ष निकाला कि इसमें एक से अधिक लोगों की संलिप्तता हो सकती है। पीड़िता के माता–पिता ने कहा कि उन्हें अपनी बेटी का शव देखने से पहले घंटों इंतजार कराया गया। पीड़िता की मां ने आरोप लगाया कि पुलिस जल्दबाजी में जांच बंद करने की कोशिश कर रही है।

पीड़िता के पिता ने यह भी खुलासा किया कि उनकी बेटी के शव का जल्दबाजी में अंतिम संस्कार कर दिया गया। उन्होंने कहा कि श्मशान घाट में तीन शव थे लेकिन उनकी बेटी का शव पहले जला दिया गया। जब जांच चल रही थी, तब कथित तौर पर अपराध स्थल के पास मरम्मत का काम शुरू हो गया।

14 अगस्त को एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के दौरान, आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में तोड़फोड़ की गई, जबकि पुलिस कथित तौर पर कवर के लिए भाग गई। मारे गए डॉक्टर के परिवार के वकील ने मुख्यमंत्री को दोषी ठहराया, कहा कि हमले में शामिल लोग टीएमसी के गुंडे थे। विरोध के डर से, कोलकाता पुलिस ने साल्ट लेक स्टेडियम में मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के बीच एक फुटबॉल मैच रद्द कर दिया। इसे सार्वजनिक असंतोष को दबाने के प्रयास के रूप में देखा गया। खेल रद्द होने के बावजूद, दोनों कट्टर प्रतिद्वंद्वियों के समर्थक मैदान में उतर आए और राज्य सरकार के खिलाफ डॉक्टरों के विरोध में शामिल हो गए। हालांकि, पुलिस ने भीड़ को तितर–बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। पिछले कुछ दिनों में, कोलकाता पुलिस ने सैकड़ों लोगों को नोटिस भेजे हैं जिन्होंने विरोध प्रदर्शन और हत्या के मामले से संबंधित सामग्री पोस्ट की थी। पुलिस ने टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर रॉय को भी तलब किया, राजनीति, समाज, कला, खेल और साहित्य के हर क्षेत्र से लोग इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। युवा, छात्र और महिला संगठन भी विरोध प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक और उसके जन संगठन पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक मांग करता है कि अदालत की निगरानी में निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों को जल्द से जल्द कानून के सामने लाया जाए, उन्हें सख्त सजा दी जाए और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जाए। पार्टी यह भी मांग करती है कि कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय कानून बनाया जाए।

RNI No.43038/1985 Postal Reg. No.: DL(C)-14/1434/2024-26 Total Page 8 Posted at : SPM, SRT Nagar PO, New Delhi-110055
Hindi Monthly Published on 25-8-2024 Posting Date: 28 & 29 of the Same Month

विपक्ष (इंडिया ब्लॉक) के नेता और सांसदों के समक्ष सीटीयू का प्रतिनिधित्व

"हम दस केंद्रीय ट्रेड यूनियनों, स्वतंत्र क्षेत्रीय महासंघों/एसोसिएशनों का मंच, जैसा कि नीचे हस्ताक्षर किए गए हैं, इंडिया ब्लॉक के पार्टी प्रतिनिधियों द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में विचार–विमर्श में आपका समर्थन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित मुद्दे रख रहे हैं।

1. भारतीय श्रम सम्मेलन (आईएलसी), एक त्रिपक्षीय निकाय पिछले 9 वर्षों से नहीं मिला है (आखिरी बार इसकी बैठक 2015 में हुई थी।)

श्रम कानूनों में सभी बदलाव और 29 केंद्रीय कानूनों के संहिताकरण को आईएलसी से पारित किए बिना आगे बढ़ाया गया। मजदूरी पर कोड 2019 में ही बिना किसी लोकतांत्रिक प्रयास के पारित कर दिया गया। तीन कोडों को तब पेश किया गया जब देश कोविड वायरस से जूझ रहा था और श्रमिक सबसे ज्यादा पीड़ितों में से थे। यह ट्रेजरी बेंच थी जिसने संहिताओं (कोडों) पर विधेयक प्रस्तावित किया और उन्होंने खुद इसे अपना लिया। उन्होंने लोकतंत्र का मजाक उड़ाया और देश के लगभग 57 करोड़ कर्मचारियों के साथ विश्वासघात किया। नियम बनाने का काम भी ऑनलाइन माध्यम से धोखाधड़ी से किया गया, जहां केंद्रीय ट्रेड यूनियनों को छद्म रूप से बहिष्कार करने के लिए मजबूर किया गया। हमारी मांग है कि भारतीय श्रम सम्मेलन (आईएलसी) तुरंत आयोजित किया जाए। श्रम संहिताओं को खत्म किया जाए और सभी संबंधित पक्षों की संतुष्टि के लिए कानूनों में बदलाव के लिए आईएलसी में बातचीत शुरू की जाए।

2. बेरोजगारी, स्वीकृत पदों पर भर्ती न होना, खतरनाक रूप से बढ़ती बेरोजगारी हमारी चिंता है। आउटसोर्सिंग, ठेकेदारी और अस्थायीकरण श्रमिकों को असुरक्षित बना रहे हैं जिससे अत्यधिक शोषण हो रहा है। निश्चित अवधि का रोजगार कर्मचारियों के जीवन में अनिश्चितता लाने का एक और तरीका है। 'हम निश्चित अवधि के रोजगार को वापस लेने की मांग करते हैं। 'स्वीकृत पदों पर भर्ती और समाप्त हो चुके पदों को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया तुरंत शुरू होनी चाहिए। 'अभूतपूर्व बेरोजगारी को दूर करने के लिए नई नौकरियों का सृजन सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। अग्निपथ योजना को समाप्त किया जाए तथा नियमित भर्ती जल्द से जल्द शुरू की जाए।

3. कार्यस्थल पर सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। हर दिन कार्यस्थल पर काम करने वाले कर्मचारी मरते हैं या विकलांग हो जाते हैं। उनमें से अधिकांश ठेके पर काम करते हैं तथा परिवार में अकेले कमाने वाले को मुआवजा नहीं मिलता तथा परिवार जीवनयापन के लिए संघर्ष करते हैं। आईएलओ द्वारा 2022 में अपने सम्मेलन में कार्यस्थल पर अधिकारों के मौलिक सिद्धांतों (एफपीआरडब्ल्यू) में आईएलओ के दो सम्मेलन संख्या 155 तथा 187 को शामिल किया गया है।

'श्रमिकों की व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर कोई भी कानून बनाते समय इन सम्मेलनों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

4. खनन, अन्वेषण, उत्खनन, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में हमारे देश के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और उपक्रमों ने हमारे देश के विकास में जबरदस्त भूमिका निभाई है। हमारे देश में सरकारी विभागों के माध्यम से सार्वजनिक सेवाओं को आम लोगों के लाभ के लिए आगे बढ़ाया गया। लेकिन पिछले दस वर्षों से सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सार्वजनिक सेवाओं का निजीकरण किया जा रहा है, जो समावेशी विकास के लिए बाधक है। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना (एनएमपी) राष्ट्रीय परिसंपत्तियों को चुनिंदा कॉरपोरेट्स को बेचने का एक और साधन है।

' हम राष्ट्रीय हित में निजीकरण पर तत्काल रोक चाहते हैं।

'एनएमपी योजना को खत्म किया जाना चाहिए।

5. 41 रक्षा आयुध कारखानों को सात कंपनियों में निगमित किया गया है, जबकि लगभग सभी कर्मचारियों ने इस कदम का विरोध किया और हड़ताल भी की। सरकार इसे घटाकर तीन निगमों तक सीमित करने पर विचार कर रही है। निजी क्षेत्र की संस्थाएँ लाभार्थी हैं। रक्षा क्षेत्र राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और इसे सरकारी क्षेत्र में होना चाहिए।

हमारी मांग आयुध कारखानों के निगमीकरण को वापस लेने की है।

6. मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए शिक्षा और स्वास्थ्य पर बजट में वास्तविक रूप से कमी की जा रही है। इस क्षेत्र पर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य शिक्षा में व्यावसायीकरण को बढ़ावा देना है, जिससे यह समाज के गरीब, निम्न और मध्यम आय वर्ग के लिए अप्राप्य हो जाएगी। नई शिक्षा नीति के पीछे की मंशा भारतीय संविधान के मूल मूल्यों के विरुद्ध शिक्षा का सांप्रदायिकरण करना भी है।

'हम नई शिक्षा नीति को खत्म करने और सभी के अधिकार के रूप में शिक्षा को बढ़ावा देने की मांग करते हैं।

'बजट आवंटन 10 प्रतिशत किया जाए, ताकि लंबित मामलों का समाधान हो सके। 'स्वास्थ्य पर बजट बढ़ाकर 6 प्रतिशत किया जाए। 'सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली का विस्तार और सुदृढ़ीकरण किया जाए।

7. बुनियादी नागरिक सेवाएं खराब हो रही हैं। श्रमिकों की बस्तियां सबसे ज्यादा प्रभावित हैं और वे अक्सर बीमार पड़ते हैं और अपना कार्यदिवस खो देते हैं। 'लोगों की न्यूनतम जीवन आवश्यकताओं के लिए इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। 'इन सेवाओं में ठेकेदारी प्रथा समाप्त की जाए।

8. न्यूनतम मजदूरी बहुत कम है। हम जीवन निर्वाह मजदूरी की संवैधानिक अवधारणा के कार्यान्वयन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हालांकि 15वीं आईएलसी सिफारिश और राप्टाकोस मामले में सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की गणना भी लागू नहीं की गई है। हमारी मांग न्यूनतम मजदूरी के रूप में न्यूनतम 26000 रुपये की है जो मूल्य सूचकांक के साथ हर पांच साल में नियमित संशोधन पर आधारित है। 8वें वेतन आयोग का जल्द से जल्द गठन किया जाए।

9. सम्मानजनक जीवन यापन के लिए सभी वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन लाभ दिया जाए। पेंशन को अधिकार माना जाए। अंशदायी नई पेंशन योजना को समाप्त किया जाए तथा गैर अंशदायी पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए। ईपीएस 95 के अंतर्गत आने वाले लोगों को न्यूनतम 9000 रुपये दिए जाएं। जो लोग किसी भी योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं, उन्हें राज्यों तथा केंद्र के बजट में से अंशदान के माध्यम से विशेष निधि कोष बनाकर 6000 रुपये प्रति माह दिए जाएं।

जन गर्जन हिन्दी मासिक ऑल इण्डिया फारवर्ड ब्लाक की केन्द्रीय समिति के लिए देवब्रत बिश्वास, पूर्व सांसद सदस्य द्वारा टी–2235/2, अशोक नगर, फैज रोड़, करोल बाग, नई दिल्ली–110005 से मुद्रित तथा प्रकाशित। दूरभाष : 28754273
संपादक : देवब्रत बिश्वास, पूर्व सांसद
मुद्रण स्थल : कुमार ओफसेट प्रिंटर्स, 381, पटपड़ गंज इण्डस्ट्रियल एरिया, दिल्ली 110092 वेबसाईट: www.forwardbloc.org
ईमेल:biswasd.aifb@yahoo.co.in
कम्प्यूटर कम्पोजिंग : प्रकाशन विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, ऑल इण्डिया फारवर्ड ब्लाक, नेताजी भवन, नई दिल्ली

जन गर्जन
नेताजी भवन,
टी–2235/2, अशोक नगर, फैज रोड़,
करोल बाग, नई दिल्ली–110005
दूरभाष: 011–28754273

जन गर्जन
ऑल इण्डिया फारवर्ड ब्लॉक का हिन्दी मासिक

सेवा में,